(b) if so, the number of branches of different commercial banks proposed to be opened in Orissa by the end of 1990;

(c) what are the names of places in Orissa where these new branches are proposed to be opened; and

(d) what are the details in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (d) The current Branch Licensing Policy covers the period from 1st April, 1985 to 31st March, 1990 which is co-terminus with the Seventh Five Year Plan. On the basis of list of identified centres received from the State Government, the Reserve Bank of India allotted a total number of 366 rural and semi-urban centres in the State of Orissa for the above period. The banks have opened branches at 146 centres upto 30th November, 1989. The banks are required to open the remaining branches at 220 centres. Besides, 20 urban/port town centres have been allotted to the banks and they have opened branches at 17 centres. No more identification of any additional centres is contemplated. As such, there is no proposal to allot further centres by Reserve Bank of India to banks during the remaining period of the Seventh Five Year Plan.

Inadequate Staff Strength in Branches of State Bank of India in Phulbani District of Orissa

369 SHRI JAGADISH JANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the different branches of State Bank of India in Phulbani District of Orissa are inadequately staffed;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government are aware of the difficulties being faced by the customers on account of this; and

(d) if so, what steps have been taken to appoint more staff in different branches of State Bank of India in Phulbani District, Orissa ?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) to (d) State Bank of India has reported that their bank's branches in Phulbani District of Orissa are adequately staffed to meet their present requirements. The Bank has also advised that although so far no adverse customer feed-back has received on account of alleged shortage of staff, the requirements of staff of branches of the bank are reviewed from time to time taking into account the buiness level and other relevant factors.

मध्य प्रदेश में बुनकरों द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने वाले धागों की कीमतों में वृद्धि

370. **श्री अजीत जोगी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में बुनकरों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे धागों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उनकी आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों की बिक्री न हो पाने के कारण उन्हें अपना कार्य बंद करने के लिए मजबूर होना पडा है;

(ख) यदि हा, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है, और

(ग) क्या इस प्रकार की समस्या का सामना देश के दूसरे क्षेत्रो में भी किया जा रहा है और यदि हा, तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो द्वारा इस मामले मे क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री और साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) गत वर्ष के दौरान पालियेस्टर स्टेपल फाइबर

विस्कोस स्टेपल फाइबर और एक्रीलिक स्टेपल फाइबर के संबंध में कीमत स्थिति संलग्न विवरण पत्र में दर्शाई गई है (नीचे देखिये) दिसम्बर, 1988 से नवम्बर 1989 की एक वर्ष की अवधि के बीच पालिएस्टर स्टेपल फ़ाइबर की कीमत स्थिर रही है, केवल जुलाई से अक्तूबर, 1989 में मामली वृद्धि हुई । विस्कोस स्टेपल फाइबर के संबंध में एक वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 6 रु. प्रति किग्रा. की वृद्धि हुई । एच डब्ल्यू एम फाइबर के संबंध में इस वर्ष के दौरान 3.74 रु. प्रति कि.ग्रा. की वृद्धि हुई । एक्रीलिक स्टेपल फाइबर के संबंध में एक वर्ष में 3 रुपये प्रति कि.ग्रा० की वृद्धि हुई । सरकार को मध्य प्रदेश में बुनाई कार्य बंद करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ये फाइबर नियंत्रित वस्तुएं नहीं हैं और उनकी कीमतें मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करती हैं । तथापि, सरकार ने एक कीमत मानीट्रिंग समिति का गठन किया, जिनकी स्थिति की समीक्षा करने के लिए समय-समय पर बैठकें होती हैं । इसके अलावा, सरकार प्रत्येक माह कीमतों को मानीटर करती है । इन फाइबरों के और उत्पादकों प्रयोक्ताओं के साथ सरकारी स्तर पर समय-समय पर बैठकें होती हैं । लेकिन मानव-निर्मित फाइबर जैसे कि डी एम टी, पी टी ए, पैराक्सलीन आदि के लिए कच्चा माल आयात किया जाता है और आयातित कच्चे माल में उतार-चढ़ाव के कारण स्टेपल फाइबर की कीमतें भी बढ़ती घटती रहती हैं । सरकार की स्टेपल फाइबर के विनिर्माण के लिए लाइसेंसिंग नीति भी उदार है ताकि सप्लाई स्थिति में सुधार हो सके । स्टेपल फ़ाइबर की कीमतें समूचे भारत में लागू होती हैं ।

विवरण

दिसम्बर 1988 से नवम्बर, 1989 तक पालियेस्टर स्टेपल फाइबर (पी० एस० एफ०), विस्कोस स्टेपल फाइबर (बी०एस०एफ०), एच०डब्ल्यू०एम० फाइबर तथा एक्रीलिक स्टेपल फाइबर (ए० एस ०एफ०) की भारित औसत कीमत दर्शाने वाला विवरण पत्र :

(रु० प्रति कि० ग्रा०)

अवधि	पी एस एफ	बी एस एफ	एच डब्ल्यू एम फाइबर	ए एस एफ
दिसम्बर, 1988	83.49	30.36	38.24	68.00
जनवरी, 1989	83.74	30.36	38.24	68.00
फरवरी, 1989	83.34	30.36	38.24	68 00
मार्च, 1989	83.28	33.43	38.24	68.00
अप्रैल, 1989	83.21	33.43	38.24	71.00
मई, 1989	83.34	33.43	38.24	71.00
जून, 1989	81.56	34.50	38.24	71.00
जुलाई, 1989	85.09	34.50	38.24	71.00
अगस्त, 1989	85.00	34.50	41.98	71.00
सितम्बर, 1989	85.98	36.55	41.98	71.00
अक्तूबर, 1989	85.56	36.55	41.98	71.00
नवम्बर, 1989	83.58	36.55	41.98	71.00